working capitas facilities. As regards non-SSI sick industrial companies, Board for Industrial and Financial Reconstruction (BIFR), a quasi-judicial body set up under the Sick Industrial Companies (Special Provisions) Act, 1985 has been adequately empowered to take necessary action for determination of preventive, ameliorative, remedial and other measures and expeditious enforcement of such measures.

Gas exploration by MNCs cleared by FIPB

6997. SHRI S. AUSTIN: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether the Foreign Investment promotion Board has allowed some American Multinational Companies to undertake gas exploration in the Eastern Coalfields Limited; and

(b) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SMT. KRISHNA SAHI): (a) and (b) Yes, Sir. M/s. Modi Meckenzie Methane Ltd., New Delhi has been allowed to set up a Joint Venture with M/s. Meckenzie India Inc. USA to undertake exploration and development of Coal bed Methan Gas in the Eastern Coal Field involving foreign direct investment.

राष्ट्रीय नवीकरण कोष का उपयोग

6968. **श्री राम जेठमलानी :**
श्री वीरेन जे० शाह :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय नवीकरण कोष को श्रमिकों के कल्याण के लिए किस तरह उपयोग किया जाना था ;

(ख) क्या यह सच है कि इस कोष से कुछ धनराशि 1992–93 और 1993–94 के दौरान श्रम-संरक्षण हेतु खर्च की गयी थी ;

(ग) यदि हां, तो उक्त वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष में इस प्रकार से खर्च की गयी धनराशि का ब्यौरा क्या है ; और

(घ) उक्त वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष में सेवानिवृत्ति संबंधी भुगतानों, सेवानिवृत्त श्रमिकों के पुनर्वास और अतिरिक्त रोजगार के अवसर पैदा करने पर खर्च की गयी धनराशि का ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) भारतीय उद्योग के प्रौद्योगिकीय उत्थान और आधुनिकीकरण से प्रभावित श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु राष्ट्रीय नवीकरण निधि की स्थापना सरकार द्वारा फरवरी 1992 में की गई थी । अन्य बातों के अलावा यह निधि युक्तिकृत श्रमिकों को मुआवजे का भुगतान करने और उन्हें परामर्श तथा पुनः प्रशिक्षण देने के वास्ते धन उपलब्ध कराएगी ।

(ख) से (घ) सर्वप्रथम राष्ट्रीय नवीकरण निधि से केन्द्र सरकार के उपक्रमों को स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति योजनाएं लागू करने हेतु सहायता दी गई थी । केन्द्र सरकार के विभिन्न उपक्रमों में स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति योजना लागू करने के लिए संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों द्वारा दी गयी राशि 1992–93 में 650.34 करोड़ रु० तथा 1993–94 में 548.67 करोड़ रु० (अनंतिम) थी । इसमें वस्त्र क्षेत्र के केन्द्र सरकारी उपक्रमों की अपेक्षित अंतरिम नकदी आवश्यकता भी शामिल है ।